SHRI K. LAKKAPPA: Sir, I seek your protection. He is not answering. (*Interruptions*)

DR. PRAPAT CHANDRA CHUNDER: Sir, the question was relating to medium of instructions through regional languages. It has nothing to do with non-regional language. (*Interruptions*).

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, I seek your protection. I seek the protection of the Chair. The government is evading to answer my question. They have no language policy. (*Interruptions*).

चौधरी बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट हुई थी कि मीडियम आफ़ इंस्ट्रक्शन जो हैं वह विश्वविद्यालय थोप नहीं सकते ? उस फ़ैसले के बाद क्या सरकार कदम उठाएगी कि जो रीजनल लैंगुएज हैं, उनको यूनिवर्सिटियां लागू करें ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : उच्चतम न्यायालय ने जो राय दी थी, वह राय डी० ए० वी० कालेज, भटिण्डा **बनाम** पंजाब यूनिवर्सिटी एण्ड अदर्स, रिट पेटिशन्स नं० 353 और 354 आफ़ 1970 में दी थी और उसमें संविधान की धारा 29 और 30 पर बहस चली थी । उसके बाद न्यायालय ने यह कहा था कि मातृ-भाषा के अलावा और कोई दूसरी भाषा अल्प समुदाय पर जोर जबर्दस्ती लागू नहीं की जा सकती ।

गुजरात में सिंचाई के अन्तर्गत भूमि

*606. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सिंचाई के मामले में पीछे है;

(ख) यह बात सुनिश्चित कराने के लिये कि राज्य सिंचाई के मामले में पिछड़ा न रहे केन्द्रीय सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है; और

(ग) गुजरात में कितनी भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई जाने की सम्भावना है और कब तक ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) 19 per cent of the total cropped area in the State of Gujarat has been provided with irrigation facilities as compared to the national average of about 28 per cent.

(b) The State Government have taken up a number of major, medium and minor irrigation schemes and the financial allocation for irrigation programme is being raised from plan to plan. Major rivers of the State except the Narmada have been generally harnessed and groundwater exploitation is stepped up on a scientific basis.

(c) The State Government have assessed that in the ultimate stage when all technically and economically feasible schemes (excluding Narmada) are completed, the total irrigation potential of 2.64 million hectares will be created. An additional potential for about 0.12 million hectares would also be available from the four new projects of Gujarat in Narmada basin, agreement in respect of which was reached in March, 1975 in a meeting between the four States with assistance of the Government of India, pending the Tribunal's decision and without prejudice to their claims before the Tribunal. Subject to availability of funds these schemes (including above 4 schemes of Narmada basin but excluding other schemes of this basin) will be completed by the end of the Seventh Five Year Plan.

श्री धर्मसिंह भाई पटेल : स्टटमेंट में बताया गया है कि गुजरात में 19 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं। गुजरात सरकार की ओर से जो आंकड़े मिले थे उनमें बताया गया था कि वहां कुल चार प्रतिशत जमीन में सरकार की ओर से सिंचाई होती है और नौ प्रतिशत किसान अपनी ओर से, निजी तौर पर सिंचाई की व्यवस्था के अन्तर्गत हैं। इस प्रकार से तेरह प्रतिशत जमीन में ही गुजरात में सिंचाई होती है। मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात में फसल योग्य कितनी जमीन है और कितने हैक्टर जमीन में अब सिंचाई होती है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : एक्चुअल फसल योग्य जमीन वहां पर 101 लाख हैक्टर है जिसमें से सिंचाई वाली जो जमीन है वह 19.4 लाख हैक्टर है। इसका परसेंटेज बन जाता है 19.2।

श्री धर्मसिंह भाई पटेल : भाग ख के उत्तर में बताया गया है कि नर्मदा को छोड़ कर गुजरात की चार नई परियोजनाएं बनने वाली हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन योजनाओं को कब मंजूरी दी गई है और जिसको नहीं दी गई है उसको कब दी जाएगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इनमें से तीन योजनाएं मंजूर हो गई है। रामी को 3-5-75 को मंजूरी दी गई है, सुखी को 1-2-77 को और कर्जन को 18-5-77 को। एक रह गई है हैरान और इसके लिए मॉडिफाइड रिपोर्ट का इन्तजार है।

SHRI D. B. PATIL: Part (b) of the question is not replied to. The question is: "whether the measures taken or proposed to be taken by the Central Government to ensure that the State does not remain backward in irrigation;" This part has not been answered. I also want to know whether the Gujarat State is lagging far behind in so far as irrigation is concerned.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: A high priority is given to the development of irrigation in this State. Many schemes are in progress. Many new schemes are being processed. Some new projects and proposals have been received. They are being processed.

श्री राघवजी : क्या सरकार को जानकारी है कि वर्षा तथा सिंचाई के साधनों के घोर अभाव के कारण गुजरात के कच्छ जिले में लगातार अनेक वर्षों से सूखा और अकाल बना हुआ है जिससे वहां का जन जीवन भारी खतरे में पड़ जाता है ? केन्द्रीय सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कोई योजना बनाई है या बनाने का विचार करेगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : माननीय सदस्य ने जो कच्छ एरिया में वर्षा के बारे में कहा है वह ठीक है। उस इलाके के लिए कोई बहुत बड़ा प्लान अभी तक नहीं बन सका है। इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री अनन्त दवे : सवाल यह था :

"the measures taken or proposed to be taken by the Central Government to ensure that the State does not remain backward in irrigation".

But what are the measures proposed by the Central Government have not been mentioned in the statement.

क्या मैज़र्ज़ लिए गए हैं और क्या कुछ प्रोपोज किया गया है यह जवाब कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं है। क्या मंत्री महोदय इस पर रोशनी डालेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : 1977-78 के लिए मेजर और मीडियम इरिगेशन प्राजैक्ट्स के लिए 70 करोड़ रुपया रखा गया है और जहां तक माइनर इरिगेशन प्राजैक्ट्स का तालुक है उनके लिए जहां पिछली बार तीस करोड़ था वहां अब 48 करोड़ रखा गया है।

Under the Centrally sponsored for strengthening the State Surface Water and Ground Water

के लिए अभी अभी जून 1977 में 75 लाख 91 हजार रुपया और सैंकशन किया गया है ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : हमारे देश में टोटल जो जमीन है उस में से कितनी सिंचित है और कितनी असिंचित ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : टोटल क्राप्ड एरिया देश में 1695 लाख हैक्टर है और उस में से जो सिंचित है वह 474 लाख हैक्टर है । यह कोई 28 प्रतिशत बनता है ।

श्री लालजी भाई : सम्पूर्ण गुजरात में ऐसा कोई सर्वे कराया है कि कितने एकड़ जमीन सिंचाई में आ रही है, और सम्पूर्ण जमीन को कब तक पूरी सिंचाई में ला सकेंगे, केन्द्रीय सरकार इस बारे में क्या मदद कर रही है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जो इस वक्त पोज़ीशन है वह मैंने जैसा बताया 19.2 परसेन्ट है । जो इस वक्त स्कीम्स चल रही हैं उन सब के नीचे 26.40 लाख हैक्टेयर हो जायेगी । लेकिन जिस एक बड़ी नदी नर्मदा योजना पर झगड़ा चल रहा है कई स्टेट्स में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान का, उसके बन जाने के वक्त और रकबा इस क्षेत्र का पानी के नीचे आ जायेगा ।

किछऊ बांध

*607. **श्री राम लाल राही** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना परियोजना को जल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए किछऊ बांध के निर्माण की एक योजना तैयार कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक क्रियान्वित की जायेगी और उस पर कितना खर्च आयेगा ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Government of Uttar Pradesh had submitted a report on Kishau Dam project in 1965 which envisaged construction of 770 feet high dam across the river Tons, a tributary of the Yamuna for power generation and use of regulated releases for water supply to Delhi and for irrigation from Yamuna. The project was estimated to cost about Rs. 100 crores. The proposals were examined and the State Government was advised to carry out investigations at alternative dam sites and up-date the project estimate. The modified report has not so far been received from the State Government. The question regarding sharing of cost and benefits of this project by other States in the Yamuna basin would also need to be decided.

(b) The implementation of the scheme can be considered after the project report is received from the State Government and the project is found technically feasible and economically viable and funds made available by the concerned States.

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट पटल पर रखी गई है यह कब बनी थी और कितनी लागत की बनी थी, और अब कौन सी रुकावट पड़ी जिसकी वजह से यह रुक गई ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस योजना का बहुत लम्बा इतिहास है । यह 1940 में पहली दफ़ा सोची गई थी और पहली दफ़ा पंजाब सरकार ने 1944 से 1946 तक इस पर कुछ थोड़ा सा इन्वेस्टीगेशन किया था । उसके बाद फिर प्रोमीलिमीनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी 1965 में उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसके मुताबिक यह 95 करोड़ रु० का प्रोजेक्ट था और 770 फ़ीट उंचा बांध बनना था । लेकिन बाद में यह देखा गया